भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4973

(सोमवार, 23 मार्च, 2026/2 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत मासिक वृत्तिका

4973. श्री बाबू सिंह कुशवाहाः
श्री देवेश शाक्यः
श्री नीरज मौर्यः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि प्रधान मंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत निर्धारित 25,000 रुपये के मासिक वृत्तिका को न्यूनतम मजदूरी और महानगरीय क्षेत्रों में रहने की लागत से काफी कम माना जाता है जिसके कारण कई युवाओं के लिए बड़े शहरों में इंटर्नशिप करना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजना के प्रारंभ से अब तक देशभर में इस योजना के अंतर्गत कुल कितने युवाओं ने आवेदन किया है और उनमें से कितने युवाओं को कंपनियों से इंटर्नशिप के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कितने युवा वास्तव में उक्त इंटर्नशिप में शामिल हुए हैं;
(ग) उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित 10,831 करोड़ रुपये की कुल निधियों में से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी की गई और खर्च की गई/उपयोग की गई;
(घ) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज, इटावा, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज और जौनपुर जिलों के युवाओं के लिए स्थान की विसंगति एक बड़ी बाधा बन रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का स्थानीय समूहों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): पीएमआईएस इंटर्न के लिए मासिक वित्तीय सहायता मार्च 2026 से 9000 रुपये निर्धारित कर दी गई है। इसमें से, प्रत्येक माह, प्रत्येक इंटर्न को दी जाने वाली कुल मासिक सहायता राशि में से 900 रुपये कंपनी अपनी सीएसार निधि या स्वयं की निधि से देगी और सरकार शेष 8100 रुपये इंटर्न

के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा करेगी। यदि कंपनी 900 रुपये से अधिक मासिक सहायता देना चाहती है, तो वह अपने स्वयं की निधि से ऐसा कर सकती है।

(ख): पीएम इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के पहले राउंड में, लगभग 1.81 लाख अभ्यर्थियों से 6.21 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। साझेदार कंपनियों ने 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों को 82,000 से अधिक इंटर्नशिप प्रस्ताव दिए और 8700 से अधिक इंटर्न उनकी इंटर्नशिप में शामिल हुए।

पीएम इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे राउंड में 2.14 लाख से अधिक आवेदकों से 4.55 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। साझेदार कंपनियों ने 71000 से अधिक अभ्यर्थियों को 83000 से अधिक प्रस्ताव दिए हैं और 7300 से अधिक इंटर्न उनकी इंटर्नशिप में शामिल हुए हैं।

(ग): वित्त वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए स्वीकृत और उपयोग की गई राशि का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ): उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लिए प्रस्तावों को स्वीकार न किए जाने अथवा कम ज्वाइनिंग दरों का विश्लेषण किया गया है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन और फीडबैक सर्वेक्षण, कॉल सेंटर द्वारा अभ्यर्थियों को किए गए आउटबाउंड कॉल और अभ्यर्थियों, उद्योग और उद्योग संघों और राज्य सरकारों जैसे विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, कम स्वीकृति/ज्वाइनिंग के देखे गए कुछ कारण नीचे दिए गए हैं:

- स्थान एक महत्वपूर्ण कारण है और अभ्यर्थियों द्वारा इंगित आदर्श यात्रा दूरी 5-10 किमी के बीच है।
- 12 महीने की इंटर्नशिप अवधि सामान्य कौशल कार्यक्रमों की तुलना में अधिक है।
- कुछ अभ्यर्थियों को प्रस्तावित भूमिकाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है।

(ङ): पीएमआईएस पायलट प्रोजेक्ट के लिए मौजूदा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनियां अपनी कंपनी में देश भर में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर सकती हैं या यह अपनी अग्र और पश्च आपूर्ति श्रृंखला (जैसे नेटवर्क संस्थाएं/सहायक कंपनियां/आपूर्तिकर्ता/विक्रेता, आदि) या अपने समूह की अन्य कंपनियों/संस्थानों में कंपनियों/एमएसएमई के साथ साझेदारी कर सकती हैं।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 23.03.2026 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4973 से संदर्भित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए 28.02.2026 तक स्वीकृत और उपयोग की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

				(राशि करोड़ रुपये में)
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन और अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	2025-26	10831.07*	526	87.46

*मुख्य योजना के लिए मंत्रालय को 10831.07 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तथापि, मुख्य योजना शुरू नहीं की जा सकी और पायलट प्रोजेक्ट को जारी रखा गया है।

*****